RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 030
दि. 02.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

अमेरिका में 4,000 करोड़ का लोन फ्रॉड: भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगा बड़ा आरोप, टेलीकॉम साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरा

(जीएनएस)। अमेरिका में भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर करीब 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपये के विशाल वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले ने वहां के कॉर्पोरेट जगत को हिला कर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मभट्ट ने अपनी कंपनियों के खातों में फर्जी ग्राहक और फर्जी इनवॉइस दिखाकर अमेरिकी बैंकों और निवेश कंपनियों से सैकड़ों मिलियन डॉलर का लोन हासिल किया। यह मामला उन हाई-प्रोफाइल लोन फ्रॉड की याद दिलाता है जिनमें भारत के नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कारोबारी शामिल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह मामला अब अमेरिका की धरती पर सामने आया है, और इसमें एक बार फिर एक भारतीय मूल के उद्योगपति का नाम शामिल है।

बंकिम ब्रह्मभट्ट अमेरिका स्थित Broadband Telecom और BridgeVoice नामक कंपनियों के मालिक हैं। इन दोनों कंपनियों को उन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी Bankai Group के तहत संचालित किया। यह समूह टेलीकॉम सेक्टर में वैश्विक स्तर पर सक्रिय रहा है और दावा करता था कि वह सैकड़ों देशों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और कॉल रूटिंग जैसी सेवाएं देता है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लैकरॉक (BlackRock) की प्राइवेट क्रेडिट शाखा HPS Investment Partners और कई अन्य अमेरिकी ऋणदाताओं ने दावा किया है कि बंकिम ब्रह्मभट्ट की कंपनियों ने "फर्जी ग्राहकों" और "झूठे इनवॉइस" बनाकर बड़े पैमाने पर कर्ज लिया और फिर उसका पैसा विदेशों में भेज दिया। इन नकली वित्तीय रिकॉर्ड्स को बैंक और निवेशकों के सामने लोन कोलैटरल (गिरवी संपत्ति) के रूप में पेश किया गया ताकि अधिक फंडिंग मिल सके।

फ्रॉड की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब HPS ने अपनी शुरुआती जांच के लिए डेलॉयट (Deloitte) को नियुक्त किया। बाद में, ऑडिट फर्म CBIZ को भी जांच में शामिल किया गया। जुलाई 2025 में एक कर्मचारी को कुछ संदिग्ध ईमेल आईडी मिलीं, जो कंपनी के कथित ग्राहकों से जुड़ी हुई लग रही थीं। जब उन ईमेल्स की जांच की गई, तो पता चला कि वे असली कंपनियों के नाम से मिलते-जुलते फर्जी डोमेन से बनाए गए थे। इससे यह साफ हो गया कि बंकिम ब्रह्मभट्ट और उनकी टीम ने एक संगठित धोखाधड़ी तंत्र खड़ा किया

था जो कई महीनों या संभवतः वर्षों से चल रहा था।

जब यह जानकारी बंकिम ब्रह्मभट्ट को दी गई, तो उन्होंने इसे "साधारण गलती" बताते हुए नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जब जांच गहराई में पहुंची, तो उन्होंने फोन कॉल्स और ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया। स्थिति तब और संदिग्ध हो गई जब HPS के अधिकारी न्यूयॉर्क के Garden City इलाके में स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। वहां न तो कोई कर्मचारी मौजूद था और न ही कार्यालय खुला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई हफ्तों से कोई वहां नहीं आया था।

अगस्त 2025 में ब्लैकरॉक और अन्य बैंकों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि बकाया है। उसी महीने 12 अगस्त को उन्होंने खुद को दिवालिया (Bankrupt) घोषित कर दिया और उनकी कंपनियों ने अमेरिकी कानून के तहत Chapter 11 में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी।

जांच में सामने आया कि इस लोन की रकम का एक बड़ा हिस्सा भारत और मॉरिशस जैसे देशों में ट्रांसफर किया गया। अमेरिकी एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पैसा किन खातों और कंपनियों में पहुंचाया गया और क्या इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी काम कर रहा था।

बंकिम ब्रह्मभट्ट ने 1990 के दशक में Bankai Group की स्थापना की थी और तीन दशकों तक उन्होंने खुद को वैश्विक टेलीकॉम जगत में एक भरोसेमंद चेहरा के रूप में पेश किया। उनकी कंपनी अंतरराष्ट्रीय कॉल रूटिंग, वॉइस ओवर IP (VoIP) सेवाओं और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में सक्रिय थी। कंपनी का दावा था कि वह दुनिया के 150 से अधिक देशों में काम कर रही है।

लेकिन जब यह फ्रॉड उजागर हुआ, तो अचानक ही उनका LinkedIn प्रोफाइल गायब कर दिया गया, वेबसाइट्स ऑफलाइन हो गईं और कंपनी के आधिकारिक संपर्क ठप पड़ गए। अब तक बंकिम ब्रह्मभट्ट का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, न ही उनके ठिकाने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी है।

अमेरिकी अदालत में यह मामला फिलहाल विचाराधीन है, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह आने वाले समय में अमेरिका के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े टेलीकॉम फ्रॉड मामलों में से एक साबित हो सकता है।

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर वैश्विक फाइनेंस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद है, और क्यों बार-बार बड़े कॉर्पोरेट नाम भरोसे का दुरुपयोग करके अरबों डॉलर की ठगी करने में सफल हो जाते हैं।

पंजाब में अखबार वितरण पर असर — पुलिस ने सुरक्षा जांच के लिए रोके समाचार पत्र ढोने वाले वाहन, कई जिलों में सप्लाई घंटों हुई देर से

(जीएनएस)। चंडीगढ़। पंजाब के कई जिलों में शनिवार की सुबह आम दिनों की तरह अखबार पाठकों तक समय पर नहीं पहुंच सके। इसका कारण था पुलिस की ओर से चलाया गया अचानक सुरक्षा जांच अभियान, जिसमें अखबार ढोने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। परिणामस्वरूप, लुधियाना, होशियारपुर, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, मुकतसर और अहमदगढ़ समेत कई इलाकों में सुबह के अखबार देर से पहुंचे या कई जगह बिल्कुल नहीं पहुंचे।

राज्य के स्पेशल डीजीपी (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने इस कार्रवाई पर सफाई देते हुए कहा कि यह जांच किसी भी मीडिया संस्था को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं की गई थी। बल्कि यह कदम विशेष सुरक्षा इनपुट्स के आधार पर उठाया गया था। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ अखबार वितरण वाहनों का इस्तेमाल नशा, हथियार या हवाला धन की तस्करी में किया जा सकता है। इसी वजह से राज्यभर में अचानक जांच का आदेश दिया गया।

अर्पित शुक्ला ने कहा, "यह कार्रवाई केवल सुरक्षा कारणों से की गई। हमारा उद्देश्य किसी अखबार की सप्लाई रोकना नहीं था। जिन वाहनों की जांच पूरी हो गई, उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया है। यह पूरी

तरह एहतियाती कदम था ताकि किसी भी संभावित गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।"

लुधियाना और होशियारपुर में सख्त जांच, अहमदगढ़ में नाराज़ पाठक

लुधियाना और होशियारपुर से मिली रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने शनिवार तड़के कई अखबार वैनों को रोककर उनकी गहन जांच की। कई जगह ड्राइवरों और हेल्परों से पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज़ों की भी जांच हुई। इन कार्रवाइयों के चलते अखबारों की वितरण श्रृंखला कई घंटों तक ठप रही।

अहमदगढ़ में सुबह नौ बजे तक अखबार नहीं पहुंचने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराज़गी जताई। स्थानीय निवासी महावीर गोयल ने कहा कि "हम रोज़ की तरह सुबह अखबार का इंतज़ार करते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दोपहर तक कोई पेपर नहीं आया।" लोगों ने इसे "अभूतपूर्व स्थिति" बताया और कहा कि आतंकवाद के दौर के बाद यह पहला मौका है जब पूरे राज्य में एक साथ अखबारों की आपूर्ति इतनी गंभीर रूप से बाधित हुई है।

अमृतसर, फरीदकोट, मुकतसर और पटियाला में भी असर

अमृतसर, फरीदकोट और श्रीमुक्तसर साहिब जिलों से भी अखबारों के समय पर न पहुंचने की खबरें आई हैं। वहीं, पटियाला में सुबह स्थानीय भाषा के अखबार ले जाने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस ने कई गाड़ियों को रोका और उनकी तलाशी ली, हालांकि जांच पूरी होते ही उन्हें आगे जाने दिया गया।

छोटे कस्बों जैसे समाना और पातड़ां में भी सप्लाई देर से पहुंची। स्थानीय वितरक जसवंत सिंह ने बताया कि "हर दिन सुबह 6 बजे तक पेपर पहुंच जाता है, लेकिन आज जांच के कारण गाड़ियां करीब 9 बजे आईं। इससे वितरण पूरा दिन बाधित रहा।"

प्रशासन ने दिया आश्वासन, वितरण जल्द सामान्य होगा

राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सभी जिलों में जांच अभियान फिलहाल समाप्त कर दिया गया है और रविवार से अखबारों की सप्लाई सामान्य करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। पुलिस ने कहा है कि भविष्य में मीडिया वितरण नेटवर्क को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए विशेष समन्वय प्रणाली तैयार की जाएगी।

इस घटना ने जहाँ एक ओर पाठकों को असुविधा में डाला, वहीं दूसरी ओर इसने राज्य में सुरक्षा एजेंसियों की सजगता को भी उजागर किया। प्रशासन का कहना है कि ऐसी जांचें जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, हालांकि आगे से कोशिश रहेगी कि जनसंचार के माध्यमों पर इनका प्रभाव न्यूनतम पड़े।

आंध्र प्रदेश में एकादशी पर बड़ा हादसा — वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से नौ श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया गहरा शोक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रविवार को एकादशी के पावन अवसर पर एक भयावह हादसा हो गया। श्रीकाकुलम के प्रसिद्ध काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुबह पूजा-अर्चना के दौरान अचानक मची भगदड़ में कम से कम नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब हजारों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए थे और भीड़ एकदम से अनियंत्रित हो गई।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एकादशी के दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। लोग दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। इसी दौरान, प्रवेश द्वार के पास अचानक धक्का-मुक्की शुरू हुई और कुछ लोग गिर पड़े। गिरते ही भीड़ ने संतुलन खो दिया और भगदड़ मच गई। देखते ही देखते मंदिर परिसर अफरातफरी में बदल गया।

11:30 बजे के करीब मचा हड़कंप

कासीबुग्गा उप-मंडल प्रभारी डीएसपी लक्ष्मण राव ने जानकारी दी कि हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, जब दर्शन के लिए मुख्य द्वार खोला गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि व्यवस्थाओं की कमी और अत्यधिक भीड़ के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय

पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिए जांच के आदेश

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे "हृदय विदारक घटना" बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की खबर अत्यंत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर मुझे गहरा दुख है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।"

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों को हरसंभव बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

नारा लोकेश ने भी जताया शोक, कहा — "गहरे सदमे में हूं"

मुख्यमंत्री के बेटे और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने भी हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह "गहरे सदमे" में हैं। उन्होंने कहा, "इस एकादशी के दिन हम सब गहरे दुख में हैं। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से घायलों की मदद में जुटे हैं।" उन्होंने स्थानीय विधायक और अधिकारियों से बातचीत कर प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।

मंदिर परिसर में मची अफरातफरी, दर्शन स्थगित

हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। कई श्रद्धालु अपने परिजनों को खोजते हुए इधर-उधर दौड़ते नजर आए। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार बंद करा दिए और दर्शन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। राहत कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विशेष व्यवस्था की।

स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिवारों को सूचित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा जल्द की जाएगी।

इस घटना ने पूरे आंध्र प्रदेश को झकझोर दिया है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले वेंकटेश्वर मंदिर में इस तरह की त्रासदी ने प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता और धार्मिक संगठनों ने मांग की है कि भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतज़ाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हों।

एआई बना दुनिया की सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली तकनीक तीन साल में एक अरब लोगों ने किया इस्तेमाल, भारत 65वें स्थान पर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंसान की सोच और तकनीक का संगम कहलाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) ने इतिहास रच दिया है। माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई डिफ्यूजन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एआई मानव इतिहास की सबसे तेजी से अपनाई गई तकनीक बन चुकी है। केवल तीन साल से भी कम समय में दुनिया के एक अरब से अधिक लोगों ने इस तकनीक को अपने जीवन और कामकाज का हिस्सा बना लिया है।

एआई की लोकप्रियता ने इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के हर महाद्वीप में एआई के उपयोग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है — कहीं यह शिक्षा, कारोबार और शासन में उपयोग हो रहा है, तो कहीं कला, मनोरंजन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नई क्रांति ला रहा है।

कैसे किया गया अध्ययन

यह अध्ययन Microsoft AI for Good Lab ने किया, जिसमें ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini और Midjourney जैसे प्रमुख एआई टूल्स से प्राप्त उपयोगकर्ता डाटा का विश्लेषण किया गया। शोध का उद्देश्य यह समझना था कि किन सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एआई को अपनाने की गति को प्रभावित किया।

भारत में एआई अपनाने की दर सिर्फ 14.2%

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई अपनाने की दर 14.2 प्रतिशत है, जिससे भारत 65वें स्थान पर है।

जबकि एआई शोध और तकनीकी कंपनियों की तेजी से बढ़ती उपस्थिति के बावजूद भारत में इसका उपयोग अभी भी सीमित है।

दूसरी ओर, यूएई (59.4%), सिंगापुर (58.6%), नॉर्वे (45.3%) और आयरलैंड (41.7%) जैसे देश एआई अपनाने में अग्रणी हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन देशों में भले ही शीर्ष स्तरीय एआई अनुसंधान केंद्र न हों, लेकिन वहां के नागरिकों ने इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा तेजी से बना लिया है।

ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ

रिपोर्ट में एआई उपयोग को लेकर आर्थिक असमानता भी स्पष्ट हुई है। ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) में एआई अपनाने की दर ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की तुलना में लगभग दो गुना है।

जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 20,000 डॉलर से कम है, वहां यह अंतर और गहरा हो जाता है।

विकसित देशों में कामकाजी वर्ग का आधे से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रहा है — जैसे ऑफिस में उत्पादकता बढ़ाने, कंटेंट निर्माण या डाटा विश्लेषण के लिए। वहीं, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में यह दर 10 प्रतिशत से भी कम है।

भाषा और संसाधन बनीं सबसे बड़ी बाधाएं

रिपोर्ट के अनुसार, भाषा एआई अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। मालावी, लाओस या नेपाल जैसे देशों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं में एआई टूल्स का सीमित सपोर्ट है, जिससे वहां के लोग इन तकनीकों से लाभ नहीं उठा पा रहे। साथ ही, सीमित डिजिटल साक्षरता, बिजली आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी भी बाधक बन रही है।

दुनिया की आधी आबादी अब भी एआई से दूर

रिपोर्ट का सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि दुनिया के लगभग चार अरब लोग, यानी मानवता का आधा हिस्सा, आज भी एआई तकनीक तक नहीं पहुंच सका है।

इसका मुख्य कारण बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और डिजिटल स्किल्स की कमी है। जहां ये तीनों आधार मजबूत हैं, वहां एआई तेजी से फैल रहा है — जैसे अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में — जबकि जहां इनकी कमी है, वहां एआई अब भी सीमित दायरे में है।

तकनीकी क्रांति का नया अध्याय

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में एआई न केवल व्यवसाय या शोध के क्षेत्र में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हो जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि यह तकनीक मानव सभ्यता के इतिहास में इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन साबित हो सकती है — और अगर डिजिटल विभाजन को पाटा गया, तो अगली पीढ़ी का भविष्य 'एआई-सक्षम दुनिया' में आकार लेगा।

संपादकीय

जहरीली हवा में घुटती सांसें

दशकों से मीडिया व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग तथा संगठन, जिस प्रदूषण संकट के प्रति चेताते रहे हैं, उसके घातक परिणाम अब साफ सामने नजर आने लगे हैं। विडंबना यह है कि देश की राजधानी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही नहीं, अब देश के तमाम बड़े-छोटे शहरों से भी जानलेवा प्रदूषण की खबरें आ रही हैं। इस घातक व मारक संकट की पुष्टि बहुचर्चित मेडिकल जर्नल लैंसेट की हालिया रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट दावा करती है कि देश की हवा में 2010 की तुलना में साल 2022 तक प्रदूषणवाहक पीएम 2.5 कणों की मात्रा में 38 फीसदी तक का बढ़ावा हुआ है। जिसका घातक प्रभाव यह है कि करीब सत्रह लाख लोग असमय काल-कवलित हो चले हैं। इससे होने वाला आर्थिक नुकसान अलग है। यह कहना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। बहुत संभव है कि सरकारें इन आंकड़ों पर सहमति न जताएं, लेकिन दीपावली के बाद दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के विभिन्न शहरों में प्रदूषण जिस घातक स्तर तक पहुंचा है, वह हालात के गंभीर होने की ओर इशारा तो करता ही है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का खिताब भी दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्पतालों में प्रदूषणजनित रोगों का उपचार कराने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जीवन के संघर्ष में रोजी-रोटी की कवायद में जुटे लोगों को यह अहसास भी नहीं होता है कि वे दिन में कितनी जहरीली हवा निगल रहे हैं। हमारे शहर केंद्रित विकास की विसंगितयां भी शहरों में प्रदूषण का दायरा बढ़ा रही हैं। शहरों में उगते कंक्रीट के जंगल न केवल हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं बल्कि वाहनों के सैलाब को भी बढ़ावा दे रहे हैं। विडंबना यह है कि इसके बावजूद राजनीतिक दलों व सरकारों में वह इच्छाशक्ति नजर नहीं आती, जो इस संकट के कारगर समाधान की राह दिखाती हो।

निश्चित तौर पर प्रदूषण संकट की यह जानलेवा स्थिति हमें शर्मसार करने वाली है। यह हमारी सामूहिक विफलता की तसवीर भी उकेरती है। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली व निकटवर्ती शहरों में जो प्रदूषण का बड़ा संकट दिखायी देता है, आखिर उसे साल भर सतर्कता के साथ क्यों नहीं देखा जाता। देश में आर्थिक असमानता व गरीबी के चलते लाखों लोग व बच्चे उन अस्वस्थकारी परिस्थितियों में काम करने को बाध्य हैं, जो कालांतर जानलेवा रोगों का सबब बनती हैं। देश में करोड़ों बाल श्रमिक पटाखा, कालीन और अन्य सांस के रोगों का संकट बढ़ाने वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं। व्यवस्था का भ्रष्टाचार नियामक एजेंसियों को हिलने तक नहीं देता। दरअसल, यह प्रदूषण मौसमी बदलाव, पटाखों या पराली जलाने से ही नहीं पैदा होता। दरअसल, इसके मूल में शासन-प्रशासन की वह विफलता भी शामिल है, जो वातावरण को जहरीला बनाने वाले उद्योगों तथा निर्माण में उड़ने वाली धूल की सतर्क निगरानी नहीं करती। दरअसल, हमारे जीवन की कृत्रिमता व सुविधाभोगी जीवनशैली ने उन घातक गैसों को बढ़ावा दिया जो ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण की कारक बनती हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि देश की जनता इस आसन्न संकट के प्रति लगातार उदासीन बनी रहती है। वह चुनावों के दौरान न तो राजनेताओं पर इस संकट के समाधान के लिये दबाव बनाती है और न ही निजी जीवन में ऐसी कोई पहल करती है। इस तरह कहीं न कहीं इस प्रदूषण वृद्धि में हमारी भागीदारी बनी हुई है। अब भले ही कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधन के उपयोग में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हम निजी जीवन में जितनी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, उतना ही प्रदूषण धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जनता को शासन-प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि वह समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रयास करे। व्यक्ति के तौर पर हमें पटाखे व पराली जलाने वालों की निगरानी करनी होगी, ताकि प्रदूषण का स्तर कम करने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

चौथाई सदी में कितना बदला धान का कटोरा

“

एक नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ की उम्र चौथाई सदी पूरी कर चुकी है। इस राज्य के जन्म के लिए धरनारत रहे उस व्यक्ति का नाम लोग भूल चुके हैं। राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त राजनीतिक क्षितिज पर अपनी अच्छी-बुरी उपलब्धियों के साथ चमक रही है। लेकिन दाऊ आनंद अग्रवाल का संघर्ष कहीं खो गया है।

इक्कीसवीं सदी की आहट सुनाई देने लगी थी..उन दिनों इन पंक्तियों का लेखक मध्य प्रदेश-राजस्थान के एक बड़े अखबार का दिल्ली में संवाददाता था.. उस दिन खबरों का सूखा था..उसे दूर करने की नीयत से इन पंक्तियों का लेखक धरनों के लिए विख्यात जंतर-मंतर पर जा पहुंचा...वहां जाकर देखा, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग को लेकर साधारण-सा व्यक्ति धरने पर बैठा था..साथ में गिनती के विश्वासपात्र ही बैठे थे..पता चला कि धरनारत उस व्यक्ति के पास खाने तक के पैसे नहीं थे..उनसे पता चली कि रात को रोजाना अपनी क्षुधा शांत करने के लिए पास ही स्थित गुरूद्वारा बंगला साहिब या फिर रकाब जाते और वहां के लंगर से अपनी भूख शांत करते थे.. उनके साथियों का भी यही हाल था..वनोपज और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य का धरना और उसे सहारा लंगर का..मर्म को छूने वाली वह खबर थी..खबर लिखी भी, 'लंगर के सहारे चलता अलग राज्य का धरना'. खबर छपते ही रायपुर और उसके आस-पास हलचल मच गई। तब आज की तरह फोन नहीं थे..लेकिन लोग उस धरना देने वाले व्यक्ति का पता पूछने और उन तक अपनी श्रद्धा रकम पहुंचाने की जैसे होड़ लग गई.. एक नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ की उम्र चौथाई सदी पूरी कर चुकी है। इस राज्य के जन्म के लिए धरनारत रहे उस व्यक्ति का नाम लोग भूल चुके हैं। राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त राजनीतिक क्षितिज पर अपनी अच्छी-बुरी उपलब्धियों के साथ चमक रही है। लेकिन दाऊ आनंद अग्रवाल का संघर्ष कहीं खो गया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों, विशेषकर प्रबुद्ध लोगों को उनका नाम याद है भी या नहीं। उन दिनों छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख दैनिक के दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे विनोद वर्मा बताते हैं कि दाऊ के एक वक्त का भोजन अखबारों के प्रमुख दफ्तर आईएनएस बिल्डिंग की कैंटीन में होता था..जिसका खर्च विनोद वर्मा उठाते थे। यहां बता दें कि विनोद वर्मा बाद के दिनों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे।

आनंद अग्रवाल को ही क्यों, बहुत लोगों को पवन दीवान की भी याद नहीं होगी। पवन दीवान बुनियादी रूप से समाजवादी नेता थे। यह बात और है कि उन्होंने बाद में राजनीतिक दलों में खूब आवाजाही की। कभी बीजेपी के कमलधारक बने तो कभी कांग्रेस के हाथ का साथ लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। छत्तीसगढ़ अब अलग राज्य के रूप में फल-फूल रहा है। लेकिन उसे मध्य प्रदेश से अलग राज्य बनाने की पहली बार ठोस मांग करने वाले खूबचंद बघेल के नाम को कितने लोग याद करते हैं, पता नहीं। पिछली सदी के साठ के दशक के आखिरी वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ बनाया था और अलग राज्य की उन्होंने मांग को पहली बार ताकतवर सुर दिया था। जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग रखी, उनकी मांग का आधार था छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, वनोपज और खूबसूरत नजारे। सबका मानना था कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनोपज और खनिजों की वजह से छत्तीसगढ़ कहीं ज्यादा समृद्ध है, लेकिन उसका फायदा उसके निवासियों को नहीं मिल रहा है। उस पर कब्जा राज्य के दूसरे इलाके के लोगों और राजनीतिक वर्चस्व वाली ताकतों को मिल रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग 1924 में रायपुर में हुई थी। लेकिन तब देश गुलाम था, अंग्रेजी दासतां से मुक्ति तब पहला उद्देश्य था। लिहाजा यह मांग सिरे से परवान नहीं चढ़ पाई। दिलचस्प यह है कि जिन्होंने अलग राज्य की मांग रखी, राजनीतिक रूप से उनका आज कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे बिडंबना कहें कि कुछ और, यह स्थिति छत्तीसगढ़ के साथ बने उत्तराखंड राज्य की भी है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सबसे जोरदार आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल ने चलाया, उसकी कीमत भी चुकाई। मुजफ्फरनगर कांड उस कीमत की चरम परिणति कही जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड में आज उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है।

छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और वाकया याद आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव 2003 में हो रहा था। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने एक साल पहले ही शुरू कर दी थी। उन दिनों केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उस सरकार में रमन सिंह इस्पात राज्य मंत्री थे। बीजेपी ने तय किया कि उन्हें चुनावी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ भेजा जाए। रमन सिंह छत्तीसगढ़ जाना नहीं चाहते थे। दिल्ली के ललित होटल के एक कार्यक्रम में दबी जुबान से बीजेपी के इस फैसले का विरोध भी जताया था। शायद उन्हें अपने भावी किस्मत का पता नहीं था। भारी मन से वे छत्तीसगढ़ गए, लेकिन विधानसभा चुनावों में उनकी अगुआई में भारी जीत मिली। मुख्यमंत्री बने और लगातार तीन कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का उन्हें स्वर्णिम मौका मिला।

छत्तीसगढ़ ने तब से लेकर अब तक लंबी यात्रा कर ली है। छत्तीसगढ़ की पच्चीस साल की इस यात्रा में सत्रह साल तक बीजेपी का शासन रहा है, जबकि महज आठ साल कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो उसका बजट महज पांच हजार सात सौ करोड़ का था। आज राज्य का बजट एक लाख 65 हजार सौ करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार इसे गति यानी सुशासन, त्वरित अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास की थीम पर आधारित बजट बता रही है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो वहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, वहां एकमात्र मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर था। यह कॉलेज 1963 में स्थापित किया गया था और इसे रायपुर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 11 सरकारी, एक एम्स और 3 निजी कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की जा चुकी है। ये कॉलेज बन गए तो उनकी संख्या 18 हो जाएगी। कह सकते हैं कि राज्य ने मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा ली है।

छत्तीसगढ़ को लेकर एक छवि यह है कि वह छोटा राज्य है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। उसे छोटा मानने की वजह उसकी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या दो करोड़ 55 लाख से ज्यादा है। अनुमान है कि इन दिनों राज्य की जनसंख्या तीन करोड़ आठ लाख के करीब है। आम धारणा है कि छत्तीसगढ़ बिहार से भी छोटा है। बिहार की जनसंख्या करीब तेरह करोड़ से कुछ ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ रकबा के लिहाज से बिहार से डेढ़ गुना बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा कहते हैं कि छोटा राज्य होने की छवि के चलते छत्तीसगढ़ को भारतीय राजनीति का ज्यादातर हिस्सा उसे कमतर आंकता है। इस छवि को तोड़ना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

जब छत्तीसगढ़ बना था, तब उसके हिस्से मध्य प्रदेश के 16 जिले आए थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। खूबसूरत झरने, प्राकृतिक जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा और टिन का प्रचुर खनिज भंडार है। देश का तीसरा सबसे बड़ा वनाच्छादित राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसका कुल 44.24 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से ढंका पड़ा है। जाहिर है कि इनकी वजह से जहां पर्यावरण की रक्षा हो रही है, वहीं जंगल पर आधारित जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अपनी स्थापना के बाद से, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है, राज्य की जीडीपी 21,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर लगभग अब करीब 5 लाख करोड़ डॉलर की हो गई है। कभी यहां आने में बैंक हिचकते थे, लेकिन अब यहां बैंकों का जाल है। राजमार्ग और रेलवे का नेटवर्क भी राज्य में बहुत बढ़ा है। मध्य प्रदेश से अलग होते वक्त राज्य में महज चार विश्वविद्यालय थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 25 हो चुकी है। पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलों की भारी कमी थी। लेकिन अब यहां नए स्कूल खोले गए हैं और पोटाकेबिन, आश्रम और छात्रावास जैसी पहल शुरू की गई हैं। बस्तर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है, हालाँकि यह अभी अधूरा है। नक्सलवाद के चलते यहां परिवहन ढांचा सुदृढ़ नहीं था। लेकिन अब उसमें भी बदलाव आया है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई दोगुनी हो गई है। पहले राज्य की राजधानी रायपुर से सिर्फ छह उड़ानों की सुविधा थी, जो अब बढ़कर 76 हो गई है। बस्तर और सरगुजा में भी हवाई अड्डे बनाए गए हैं।

प्रेरणा

गवर्नर से बड़ी मां की आज्ञा : भारतीय संस्कारों की अमर गाथा

भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से यह सिद्ध कर देते हैं कि शिक्षा केवल डिग्रियों से नहीं, बल्कि संस्कारों से पूर्ण होती है। ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर आशुतोष मुखर्जी की, जिन्हें भारतीय शिक्षा-जगत का "बंगाल का लायन" कहा जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान, मातृभक्ति और भारतीयता का गौरव न केवल उस युग में बल्कि आज भी प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है।

यह घटना उस समय की है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेज शासन की कठोर नीतियों और सांस्कृतिक अहंकार के बीच भारतीयों के आत्मसम्मान को बार-बार चुनौती दी जा रही थी। ऐसे दौर में जब बहुत से लोग सत्ता के भय से झुक जाते थे, तब कुछ ऐसे तेजस्वी भारतीय थे जो आत्मगौरव के साथ खड़े रहना जानते थे। आशुतोष मुखर्जी उन्हीं में से एक थे — ज्ञान, चरित्र और आत्मबल के प्रतीक।

आशुतोष मुखर्जी का बचपन अत्यंत साधारण परिस्थितियों में बीता था। उनके पिता का निधन बहुत पहले हो गया था, और उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण किया। माताजी ने अपने पुत्र को यह सिखाया कि विद्या का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता और संस्कृति का पालन करना भी है। इसी मातृसंस्कार ने उन्हें इतना दृढ़ बना दिया कि जीवन में किसी भी पद या सत्ता के सामने वे कभी झुके नहीं।

समय बीतने के साथ आशुतोष मुखर्जी भारतीय शिक्षा जगत का एक तेजस्वी नाम बन गए। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, न्यायपालिका में उच्च पद पर पहुंचे और ब्रिटिश शासन के दौर में भी अपनी विद्वत्ता से अंग्रेजों को प्रभावित किया। उनकी ख्याति इंग्लैंड तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेज अधिकारी उनकी विद्वता के इतने कायल थे कि वे चाहते थे आशुतोष स्वयं ब्रिटेन जाकर वहाँ अपने विचार और ज्ञान का प्रदर्शन करें। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन स्वयं उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। कर्जन ने यह निश्चय किया कि वह आशुतोष मुखर्जी को एक विशेष शैक्षणिक दौरे पर ब्रिटेन भेजेंगे ताकि वहां की सरकार और विद्वान भारतीय शिक्षा और बुद्धिमत्ता का परिचय प्राप्त करें। उन्होंने अपने आदेश के साथ यह प्रस्ताव आशुतोष को भेजा।

परंतु आशुतोष की माताजी उस समय के पारंपरिक भारतीय संस्कारों में गहराई से आस्थावान थीं। उनके लिए "समुद्र पार" जाना यानी विदेश यात्रा करना, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि विदेश जाना हमारे परिवार की परंपरा और संस्कारों के विरुद्ध है, इसलिए तुम कभी यह कदम मत उठाना। जब लॉर्ड कर्जन का निमंत्रण आया, आशुतोष ने विनम्रता से कहा — "मैं अपनी माताजी की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकता।" यह सुनकर अंग्रेज अधिकारी पहले तो चकित रह गए, फिर उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण बहाना है। कर्जन ने गर्व भरे स्वर में कहा — "घर जाइए और अपनी माताजी से कहिए कि भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन स्वयं आपको ब्रिटेन जाने की अनुमति दे रहे हैं।"

यह वाक्य सत्ता के गर्व से भरा था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी की आत्मा उस सत्ता से कहीं ऊंची थी। उन्होंने अत्यंत शांति और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया — "महोदय, मैं आशुतोष मुखर्जी अपनी माताजी की इच्छा की उपेक्षा करके किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन कभी नहीं करूंगा, फिर चाहे वह किसी भी देश का गवर्नर जनरल हो या उससे भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।"

इस उत्तर ने लॉर्ड कर्जन को निरुत्तर कर दिया। वह भारतीय जिसे अंग्रेज "गुलाम प्रजा" कहते थे, आज उसके सामने खड़ा होकर यह कह रहा था कि एक मां की आज्ञा ब्रिटिश गवर्नर की आज्ञा से भी बड़ी है। वह क्षण ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर भारतीय संस्कारों की विजय का प्रतीक बन गया।

उस दिन के बाद से आशुतोष मुखर्जी केवल एक न्यायाधीश या कुलपति नहीं रहे — वे भारतीय आत्मगौरव के प्रतीक बन गए। उनकी यह घटना बंगाल से लेकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। हर शिक्षित भारतीय ने यह महसूस किया कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति अडिग रहे, चाहे सामने कितनी भी शक्ति क्यों न हो।

लॉर्ड कर्जन बाद में भी आशुतोष की विद्वता की प्रशंसा करते रहे, लेकिन उनके भीतर यह बात हमेशा गूंजती रही कि "जिस देश में एक पुत्र अपनी मां की इच्छा के आगे गवर्नर की आज्ञा को भी तुच्छ समझे, उस देश को कभी पराजित नहीं किया जा सकता।"

आशुतोष मुखर्जी ने जीवन भर इस सिद्धांत को निभाया। वे जब तक जीवित रहे, भारतीय शिक्षा की आत्मा को पश्चिमी प्रभाव से बचाए रखने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में भारतीय विषयों, संस्कृत और दर्शन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया और कहा — "हमारा ज्ञान पश्चिम से उधार नहीं, हमारे अपने मूल से जन्म लेता है।"

उनकी माताजी ने भले ही उन्हें विदेश नहीं जाने दिया, पर उनके संस्कारों ने आशुतोष को विश्व में भारत का गौरव बना दिया। ब्रिटिश सत्ता ने जहाँ उन्हें पुरस्कार और उपाधियाँ दीं, वहीं भारतीय जनता ने उन्हें दिल से "मां का आज्ञाकारी पुत्र" कहा — एक ऐसा पुत्र जिसने दिखा दिया कि मां की आज्ञा किसी गवर्नर या साम्राज्य से भी बड़ी होती है।

यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की आत्मा की गाथा है — वह आत्मा जो अपनी जड़ों से जुड़ी है, जो मां को देवता से भी बड़ा मानती है, और जो शक्ति, पद या विदेशी वैभव के आगे कभी झुकती नहीं। आशुतोष मुखर्जी की यह घटना आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता, श्रद्धा और मातृभक्ति के साथ जुड़ा हो।

मां की आज्ञा के आगे जब गवर्नर की सत्ता झुक गई, तब दुनिया ने समझा कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति और उसके पुत्रों की मातृभक्ति में है — और यही भक्ति भारत को हर युग में अमर बनाती आई है।

जानलेवा प्रदूषण, सरकारों की शर्मनाक नाकामी

भारत की वायु में जहर घुल चुका है। हाल ही में चिकित्सा जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह निष्कर्ष दिया है कि 2010 की तुलना में 2022 में हवा में जानलेवा साबित होने वाले पीएम 2.5 कणों की मात्रा 38 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इस वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि भारत में सत्रह लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि मानवता की उस सांस का हिसाब है जो हमारे शहरों, गांवों और जीवन से हर दिन छीनी जा रही है। प्रदूषण अब केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं रह गया है, यह हमारे विकास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के ढांचे पर गहरी चोट कर रहा है। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि 2022 की तुलना में अब वायु प्रदूषण ने और गंभीर रूप लेते हुए जानेलेवा हो गया है, क्योंकि बीते तीन वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय किए ही नहीं गए। इसका प्रमाण यह है कि इन दिनों दिल्ली समेत देश के अनेक शहर बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में हैं। यह न केवल सरकार की शर्मनाक नाकामी है बल्कि भयावह और बेहद दर्दनाक भी है। 'द लेंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ ऐंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट केवल तथ्य नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। लैंसेट की रिपोर्ट ही नहीं, अलग-अलग वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययनों ने भी कुछ इसी तरह के चिन्ताजनक आंकड़े पेश किए हैं। भारत की विशाल आबादी के कारण भी यह संख्या बड़ी हो सकती है, मगर यह समस्या गंभीर चिंतन और तत्काल निवारक कदम उठाए जाने की मांग करती है। भारत में प्रदूषण केवल औद्योगिक उत्पादन या वाहनों की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली, असंतुलित शहरीकरण और अनियोजित निर्माण से भी बढ़ रहा है। हर शहर में धूल, धुआं और अव्यवस्था की परतें जमी हैं। निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल, खेतों में पराली जलाने की आदत, घरेलू ईंधनों का अंधाधुंध उपयोग और बढ़ते वाहनों की भीड़-ये सब मिलकर वातावरण को घुटनभरा एवं जानलेवा बना रहे हैं। हमारे शहर अब सांसों के शत्रु बन गए हैं। बढ़ते प्रदूषण की पीड़ा नीति-निर्धारकों से नहीं, उन लोगों से पूछिए, जो खांसते-खांसते बेदम हो जाते हैं और आखिरकार कई के फेफड़े-हृदय उनका साथ देना बंद कर देते हैं। विडंबना यह है कि इनमें से ज्यादातर उस गलती की सजा भुगतने को अभिशप्त हैं, जो उन्होंने नहीं की।

वायु में मौजूद सूक्ष्म कण अब हर सांस में जहर बनकर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों ने न केवल हवा को जहरीला बनाया है बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव को भी कमजोर कर दिया है। इन स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन के कारण लाखों लोग असमय काल के ग्रास बन रहे हैं, लेकिन ऊर्जा नीति में सुधार की गति अत्यंत धीमी है। सरकारें बार-बार स्वच्छ ऊर्जा की बात करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लक्ष्य घोषित करती हैं, पर उनका क्रियान्वयन न के बराबर होता है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इस प्रदूषण के शिकार सबसे अधिक वे लोग हैं जो इसके निर्माता नहीं हैं। गरीब मजदूर, झुग्गियों में रहने वाले, बच्चे और बुजुर्ग-ये सभी उस वायु के दंश झेल रहे हैं जिसका लाभ अमीरों ने उठाया है। एक ताजा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, अमीर तबके का प्रदूषण में योगदान अत्यधिक है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की 'जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025' बताती है कि विश्व के सबसे धनी लोग अपनी संपत्ति और निवेशों के माध्यम से जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 41 प्रतिशत के लिए निजी पूंजी जिम्मेदार है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदूषण का असली निर्माता संपन्न वर्ग है, जबकि उसकी कीमत गरीब वर्ग अपनी सांसों और जीवन से चुका रहा है। यह असमानता केवल आय की नहीं, बल्कि पर्यावरणीय न्याय की भी है। अमीरों के पास बड़े वाहन हैं, विशाल भवन हैं, आलीशान जीवनशैली है, और वे जीवाश्म ईंधनों पर आधारित उद्योगों में निवेश करते हैं। दूसरी ओर, गरीबों के पास न तो स्वच्छ ऊर्जा है, न शुद्ध हवा। जो अमीर लोग निजी विमानों और विलासितापूर्ण संसाधनों का उपयोग करते हैं, वे एक सामान्य नागरिक की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। यह असंतुलन हमारे समाज को विषमता और अन्याय की ओर धकेल रहा है।

सरकारों की नीतिगत विफलता इस त्रासदी का दूसरा बड़ा कारण है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योजनाएं तो बनती हैं, पर उनमें न तो स्थायित्व होता है, न गंभीरता। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, निगरानी तंत्र कमजोर है, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई नगण्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा अस्पष्ट है। हर साल सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की हवा जहरीली हो जाती है, तब कुछ दिन के लिए 'आपात कदम' उठाए जाते हैं, पर जैसे ही धुंध छंटती है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। नीतियों में पारदर्शिता का अभाव और उद्योगपतियों का दबाव भी एक गहरी समस्या है। कोयला आधारित उद्योगों, पेट्रोलियम कंपनियों और निर्माण व्यवसाय से जुड़ी लॉबी सरकारों पर ऐसा प्रभाव बनाए रखती हैं कि कठोर कदम उठाना राजनीतिक दृष्टि से असुविधाजनक बन जाता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को हमेशा 'महंगा विकल्प' बताकर टाला जाता है, जबकि वास्तव में यह निवेश मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा में है।

वायु प्रदूषण का संकट केवल वातावरण में धूल और धुएं का मामला नहीं है, यह आर्थिक अन्याय, राजनीतिक असंवेदनशीलता और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। जो सरकारें जनजीवन सुधारने का वादा करती हैं, वे हवा की गुणवत्ता सुधारने में विफल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है।

अभियान

कार्तिक में तुलसी चालीसा का विशेष महत्व : श्रीहरि की कृपा से बदल जाएगी किस्मत

हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और शुभ महीना कहा गया है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश-भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। यह वही काल होता है जब वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा फैल जाती है — दीपों की पंक्तियों से जगमगाते घर, संध्याकालीन आरतियाँ, तुलसी चौरा पर जलते दीप और मंदिरों में गूंजते शंखध्वनि, ये सब मिलकर पूरे वातावरण को एक दिव्य चेतना से भर देते हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का आठवां महीना है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में श्रीहरि विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कार्तिक माह में दीपदान, स्नान, व्रत और विशेष रूप से तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं श्रीहरि की अर्धांगिनी मानी जाती हैं।

पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर अनेक रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की, तब उन्होंने देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी को अपना प्रिय बनाया। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए हर मंदिर में विष्णु प्रतिमा के आगे तुलसी पत्र का अर्पण आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी का एक पत्र भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए, तो वह सहस्त्र स्वर्णदान के समान फल देता है।

कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। तुलसी चालीसा न केवल भक्ति का एक स्तोत्र है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, समृद्धि और शुभता का संचार करती है। जब भक्त तुलसी के पौधे के सम्मुख दीपक जलाकर श्रद्धा से तुलसी चालीसा का पाठ करता है, तब उसके चारों ओर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। कहा जाता है कि इस समय श्रीहरि विष्णु और तुलसी माता स्वयं अपने भक्त के समीप उपस्थित होकर उसके पापों का नाश करते हैं।

तुलसी पूजा का समय प्रातःकाल या संध्याकाल सर्वोत्तम माना गया है। तुलसी चौरे को स्वच्छ जल से धोकर दीपक जलाना चाहिए और ताजे फूल अर्पित करने चाहिए। तुलसी माता को चंदन, हल्दी और लाल रंग प्रिय होते हैं। तुलसी चालीसा का पाठ करने से पहले "ॐ तुलस्यै नमः" मंत्र का 11 बार जप करने से मन और वातावरण दोनों पवित्र हो जाते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान रोजाना तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसका मानसिक और आध्यात्मिक जीवन भी संतुलित हो जाता है। घर में दरिद्रता, कलह, रोग और दुर्भाग्य का अंत होता है। तुलसी चालीसा की ध्वनि से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और श्रीहरि की कृपा से सौभाग्य स्थायी हो जाता है।

तुलसी माता को 'विष्णुप्रिया' कहा गया है — जो स्वयं श्रीहरि की प्राणप्रिय हैं। तुलसी की छाया में बैठकर भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में अधर्म की ओर नहीं जाता। कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, तब यह प्रतीक होता है दिव्यता और पवित्रता के मिलन का। तुलसी विवाह के बाद देवताओं का विश्राम काल समाप्त होता है और शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। कहा गया है —

"यत्र तुलसी तत्र श्रीः, यत्र श्रीः तत्र हरिः स्वयं।"

अर्थात जहाँ तुलसी है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, और जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है।

कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने से न केवल मनुष्य के कर्म शुद्ध होते हैं, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। श्रीहरि और तुलसी माता की कृपा से उसके जीवन की कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाती हैं और किस्मत मानो नया मोड़ ले लेती है।

इसलिए जो भी भक्त कार्तिक महीने में श्रद्धा और प्रेम से तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में एक नयी ऊर्जा, एक नया प्रकाश और एक नया भाग्य उदय होता है। तुलसी के समक्ष किया गया वह छोटा-सा दीप, भक्त के भीतर बसे अंधकार को मिटाकर, जीवन को श्रीहरि की कृपा से आलोकित कर देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने एकता नगर में 'भारत पर्व-2025' का प्रारंभ कराया

भारत पर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'राज्य अनेक-राष्ट्र एक', 'समाज अनेक-भारत एक', 'भाषा अनेक-भाव एक' तथा 'रंग अनेक-तिरंगा एक' मंत्र को उजागर करता है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

एकता नगर में भारत पर्व द्वारा 15 दिनों तक समग्र भारत तथा भारतीय परंपराएँ पुनर्जीवित होने वाली हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हृदय में 'स्व' का नहीं, 'समस्त' व 'राष्ट्रहित प्रथम' का ही विचार रखा है
- प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा एकता नगर को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने का विजन दिया है
- एकता नगर प्रकृति, प्रगति एवं सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण के रूप में समग्र विश्व को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की झाँकी कराता है
- प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलकर आत्मनिर्भर भारत तथा एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हों

-: 'भारत पर्व-2025' की विशेषताएँ :-

- भारत पर्व में देश के विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी
- प्रतिदिन शाम को दो-दो राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ की जाएंगी
- 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसे जाएंगे
- भारत दर्शन पैवेलियन में विभिन्न राज्यों के पैवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें उन राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाया जाएगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, आदिजाति विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा व अन्य महानुभावों की उपस्थिति में 'भारत पर्व-2025' का शुभारंभ कराया।

अखंड भारत के निर्माता तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उत्सव के हिस्से के रूप में एकता नगर में इस भारत पर्व का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह भारत पर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र 'राज्य अनेक-राष्ट्र एक', 'समाज अनेक-भारत एक', 'भाषा अनेक-भाव एक' तथा 'रंग अनेक-तिरंगा एक' को चरितार्थ करता है। इस भारत पर्व में लोगों को 'अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता' का भाव प्रदर्शित करने वाली संस्कृति की झलक मिलने वाली है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि विश्व नेता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के निर्माण द्वारा सरदार साहब को उत्तम श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब ने 562 रजवाड़ों के विलय से एक भारत का निर्माण किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विकास के मार्ग पर श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता के दशकों बाद हमें प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसने हृदय में 'स्व' का नहीं, 'समस्त' का – 'राष्ट्रहित प्रथम' का ही विचार रखा है। श्री पटेल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता के बाद वर्षों तक सरदार जयंती केवल एक परंपरागत कार्यक्रम बन गई थी, परंतु हमारे मोदी साहब ऐसे विजनरी लीडर हैं कि जो किसी को न सूझे, वह उन्हें सूझता है। मोदी साहब ने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा भारत की एकता के लिए दिए गए बहुमूल्य योगदान का यथोचित गौरव किया है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि मोदी साहब ने 2014 से सरदार साहब की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा देशवासियों को दी है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के विराट कार्य जितनी ही विराट विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यह वनवासी प्रदेश विश्व के मानचित्र पर चमका है। वही व्यवस्थाएँ, वही प्रशासन, फिर भी यदि विशिष्ट विजन हो, तो स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, यह मोदी साहब ने एसओयू एवं एकता नगर के निर्माण से सिद्ध किया है।

भारत पर्व के विषय में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस भारत पर्व में प्रतिदिन शाम को दो-दो राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ की जाएंगी। 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त; 55 हस्तकला तथा हथकरघा स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ भारत दर्शन पैवेलियन में विभिन्न राज्यों के पैवेलियन बनाए जाए हैं, जिनमें उन राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडाजी की भी इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में एकता नगर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी।

उन्होंने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत की तरह ही अनेकता में एकता की भावना हमारे उत्सवों-त्योहारों में भी साकार होती है। गुजरात का नवरात्रि – गरबा उत्सव, महाराष्ट्र का गणपति उत्सव, बिहारियों का छठ पूजा उत्सव या पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा उत्सव; ये सभी उत्सव देश में जहाँ-जहाँ उन राज्यों के मूल निवासी परिवार रोजी-रोटी के लिए आकर बसे हैं, वहाँ सभी साथ मिलकर मनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि श्री नरेन्द्रभाई की प्रेरणा से माधवपुर का मेला राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना है। यह मेला पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम भारत को जोड़ता है। श्री मोदी के मार्गदर्शन में सौराष्ट्र-तमिल संगम तथा काशी-तमिल संगम के आयोजन से भारत की एकता व अखंडता अधिक मजबूत हुई है। इसे यह भारत पर्व उजागर करता है।

इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री ने देश के राज्यों के राजभवनों में भी अलग-अलग राज्यों के स्थापना दिवस को लोगों के संग मनाए जाने के माध्यम से एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस भारत पर्व द्वारा 15 दिनों तक एकता नगर में समग्र भारत एवं भारतीय परंपराएँ पुनर्जीवित होने वाली हैं। प्रधानमंत्री की 'विकास भी, विरासत भी' संकल्पना सच्चे अर्थ में पूरी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा एकता नगर को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए विजन दिया है और यहाँ सरदार साहब की प्रतिमा के साथ-साथ अनेक पर्यटन आकार्षण आयाम जोड़े हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भी संकल्प किया है। इसके लिए उन्होंने सरदार साहब के दिखाए एकता के मार्ग पर चलकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भारत पर्व के विभिन्न स्टॉल की मुलाकात ली।

इस अवसर पर सांसद श्री जशुभाई राठवा, विधायक डॉ. दर्शनाबेन देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भीमसिंह तडवी, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएल) के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश पुरी, पर्यटन सचिव श्री राजेन्द्र कुमार, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के प्रबंध निदेशक श्री प्रभव जोशी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सीईओ श्री अमित अरोड़ा, आदिजाति विकास आयुक्त श्री आशिष कुमार, जिला कलेक्टर श्री एस. के. मोदी, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) श्री आर. बी. वाळा, पुलिस महानिदेशक श्री संदीप सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री विशाखा डबराल, एसओयू के अपर कलेक्टर श्री गोपाल

अनंत अनादि वडनगर : गुजरात सरकार की क्रांतिकारी पहल

वडनगर में देश के प्रथम भव्य वृंदावन गौचर पार्क के निर्माण की तैयारी, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा वैश्विक मॉडल

गौप्रेमी प्रधानमंत्री का जन्मस्थल बनेगा गौसेवा का तीर्थधाम

- 'गाय से गाँव' की कायापलट करने की अभूतपूर्व दूरदर्शिता
- विरासत-संस्कृति-पर्यटन-अर्थव्यवस्था का संगम
- साधारण गौशाला से बढ़कर अत्याधुनिक ग्रामीण प्रयोगशाला

(जीएनएस)। गांधीनगर, 1 नवम्बर : प्राचीन पौराणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि के रूप में विश्व विख्यात वडनगर अब इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के साथ आधुनिक युग का भी महत्वपूर्ण दर्शनीय-पर्यटन स्थल बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से मेहसाणा जिले के इस महत्वपूर्ण स्थल वडनगर को 'अनंत अनादि वडनगर' विजन के साथ वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के अनेक प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार वडनगर में अब एक बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण भव्य वृंदावन गौचर पार्क के निर्माण की क्रांतिकारी पहल करने जा रही है, जो अपनी तरह का देश का पहला वृंदावन गौचर पार्क होगा और देश एवं दुनिया के लिए वैश्विक मॉडल बनेगा। इतना ही नहीं; इस पार्क के निर्माण के बाद गौप्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मस्थल वडनगर गौसेवा तीर्थधाम के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। यद्यपि इस पार्क के नाम से प्रतीत होता है कि यह पार्क गाय से जुड़ा हुआ होगा, परंतु इसकी परिकल्पना पर दृष्टि डालने से तो पता चलता है कि यह पार्क केवल गाय से नहीं, बल्कि गाँव से जुड़ा प्रोजेक्ट है।

शासन-प्रशासन की कवायद शुरू

14.98 करोड़ रुपए यानी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रस्तावित वृंदावन गौचर पार्क के निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल प्रस्ताव के रूप में है और नगर पालिका व जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर शहरी विकास विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वृंदावन गौचर प्रोजेक्ट को अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य स्तर पर गुजरात शहरी विकास कंपनी (जीयूडीसी) इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगी, जबकि जिला स्तर व नगर पालिका स्तर पर भूमि अधिग्रहण सहित समग्र निर्माण प्रक्रिया की जाएगी।

गाय आधारित ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बनेगा पार्क

वृंदावन गौचर पार्क के नाम से इतर कि इस प्रोजेक्ट के विजन में सिर्फ गाय ही नहीं, बल्कि गाँव है। इस पार्क की परिकल्पना और इसके लक्ष्यों पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक 'गाय आधारित ग्रामीण विकास' का आदर्श मॉडल बनेगा। इस प्रोजेक्ट में 'गाय से गाँव' की कायापलट का अभूतपूर्व विजन है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का संचार करेगा। यह केवल एक गौशाला नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ग्रामीण प्रयोगशाला और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र होगी, जहाँ परंपरा और तकनीक का संगम होगा। पार्क को एक 'रूरल इनोवेशन हब' के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की इस एक प्रोजेक्ट के जरिये गाय से लेकर गाँव-किसान-पशुपालक; तक सभी के भविष्य को उन्नत बनाने की योजना है।

डेयरी विकास, रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण शामिल

प्रोजेक्ट के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य में सुधार क्षेत्र में समय पर उपचार और बेहतर पोषण से गायों की उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, दूध व डेयरी उत्पादों की बिक्री से पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाने, पशु चिकित्सा, डेयरी उद्योग, परिवहन और विपणन में नए कार्यों से रोजगार के नए अवसर सृजित करने, बायोगैस तथा जैविक खाद से प्रदूषण में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि से पर्यावरण संरक्षण करने, आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से तकनीकी उन्नति लाने, विरासत और कृषि पर्यटन के नए गंतव्य के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा देने, डेयरी उत्पादन एवं सहकारी समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से महिला सशक्तिकरण करने, गांव में एकजुटता और आत्मनिर्भरता का भाव लाकर सामुदायिक विकास करने, जैविक खाद और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर कृषि विकास करने जैसे विशाल लक्ष्य रखे गए हैं।

पर्यटनीय स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल बनेगा गौचर पार्क

इस पार्क के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य वडनगर के सड़क मार्गों को आवारा पशुओं से मुक्त बनाना है। इस पार्क में गायों के लिए चारागाह के अनुरूप घास-चारे व पानी की व्यवस्था होगी; तो इन पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। यह पार्क सीसीटीवी कैमरा निगरानी से लैस होगा। पार्क में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तथा अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पार्क में गायों की अच्छी नस्लों के पालन-पोषण के प्रयास भी किए जाएंगे। ये सारे उपक्रम इस वृंदावन गौचर पार्क को एक पर्यटनीय स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल भी बनाएंगे।

विरासत-संस्कृति-पर्यटन-अर्थव्यवस्था का संगम

यह गौचर पार्क वडनगर के प्राचीन मंदिरों, बावड़ियों, ऐतिहासिक किले और विरासत स्थलों के साथ जुड़कर एक नए पर्यटन परिपथ का निर्माण करेगा। पर्यटक यहाँ आकर ग्रामीण जीवन, पशुपालन की आधुनिक तकनीक और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को नजदीक से देख सकेंगे। यह स्थान 'एग्रो-टूरिज्म' और 'कल्चरल टूरिज्म' का नया केन्द्र होगा। पार्क में स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के लिए यहाँ बाजार और प्रदर्शनियों का आयोजन संभव होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।

गुजरात देगा पूरे देश को संदेश

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'ग्रामोदय से भारत उदय' के विज़न के अनुरूप इस प्रोजेक्ट के जरिये गुजरात पूरे देश को संदेश देगा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति भी है। जब वृंदावन गौचर पार्क अपनी पूरी भव्यता में तैयार हो जाएगा, तब यह वडनगर के लिए केवल एक सुविधा नहीं, अपितु एक नई पहचान होगा। वडनगर एक ऐसा स्थान बनेगा; जहाँ इतिहास, संस्कृति, विकास और नवाचार एक साथ साँस लेंगे।

जनसुनवाई में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई — संभल में 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, SP ने दी सख्त चेतावनी

(जीएनएस)। संभल। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। जनसुनवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने एक साथ 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये सभी पुलिसकर्मी जिले के अलग-अलग थानों में तैनात थे और जनशिकायतों के निस्तारण में उदासीनता दिखाने के दोषी पाए गए।

एसपी विश्नोई ने कहा कि यह कार्रवाई जनता के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि "जनसुनवाई में लापरवाही, शिकायतों की अनदेखी या जनता से दुर्व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुने और उसका समाधान करे।" लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में कई थानों के मुख्य आरक्षी और आरक्षी शामिल हैं। इनमें कोतवाली संभल से आरक्षी राजपाल सिंह और मुख्य आरक्षी सह चालक बलराज, थाना हयातनगर से चालक रूपचंद, आरक्षी नीरज कुमार और आशू यादव, थाना कैलादेवी से मुख्य आरक्षी अशोक कुमार और सत्येंद्र कुमार शर्मा, थाना हजरतनगर गढ़ी से आरक्षी मोहित कुमार और मुख्य आरक्षी सोवरन सिंह, थाना नखासा से आरक्षी अनिरुद्ध चौधरी और सहचालक आकाश जुरैल, थाना असमोली से आरक्षी रोबिन राठी और भोलू तोमर, तथा थाना रायसत्ती से मुख्य आरक्षी अरुण सिवाल और आरक्षी गौरव शर्मा के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त ऐंचौड़ा कम्बोह, बबराला, रजपुरा, जुनावई, धनारी, चंदौसी, बनियाठेर और कुढ़फत्तेहगढ़ थानों के कई पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में जिले में आयोजित जनसुनवाई और शिकायत निवारण बैठकों में कई मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा शिकायतकर्ताओं की बात को नजरअंदाज करने या समय पर कार्रवाई न करने की शिकायतें सामने आई थीं। एसपी ने स्वयं रिकॉर्ड और रिपोर्टों की समीक्षा की और पाया कि कुछ थाना स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गई थी। इसके बाद यह सामूहिक कार्रवाई की गई।

एसपी विश्नोई ने कहा कि जनता की शिकायतें पुलिस विभाग के लिए प्राथमिकता हैं, और किसी भी स्तर पर उपेक्षा पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी — "भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मी यदि जनता के प्रति असंवेदनशील या लापरवाह पाया गया, तो उसके खिलाफ निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक की कार्रवाई की जाएगी।"

इस कार्रवाई को जिले में पुलिस अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कार्यवाही माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इसे एक "सकारात्मक और आवश्यक कदम" बताते हुए कहा कि इससे जनसुनवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीरता बढ़ेगी, और आम जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संदर्भ में बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

राज्य सरकार फसलों को हुए नुकसान की तत्काल समीक्षा-सर्वेक्षण कर किसानों को उदारतम सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हाल ही में राज्य में हुई बेमौसम बरसात और मौसम में आए बदलाव के कारण फसलों को हुए नुकसान के संबंध में पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों की आपदा के समय उनके साथ खड़े रहने के दिशा-निर्देश दिए हैं।

राज्य में इस वर्ष असाधारण हालात में यह बेमौसम बारिश हुई है। इसके कारण किसानों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे में, राज्य सरकार का उद्देश्य संपूर्ण किसान हितैषी दृष्टिकोण के साथ किसानों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, राज्य में पिछले दो दशकों से अधिक समय में ऐसी बेमौसम बरसात नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस वर्ष ऐसी बेमौसम बारिश के कारण किसानों को जो नुकसान झेलना पड़ा है, उसकी तत्काल समीक्षा-सर्वेक्षण करके किसानों को उदारतम सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन असाधारण परिस्थितियों में हुई बेमौसम बरसात तथा उसकी व्यापकता को देखकर मुख्य सचिव और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ऐसे हालात शायद ही कभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेष संवेदनापूर्वक राज्य के किसानों के हित में प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का पंचनामा और आवश्यक कार्रवाई कर कामकाज को इस तरह से 3 दिनों के भीतर इस प्रकार पूरा करें कि किसानों को कोई परेशानी हो, और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को तुरंत भेजें। उन्होंने जिला कलेक्टरों, जिला विकास अधिकारियों और जिला खेतीबाड़ी अधिकारियों को तुरंत इस विषय में सूचित करने के आदेश दिए, ताकि किसानों को हुए नुकसान को लेकर सहयोग करने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन असाधारण हालातों और राज्य के किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पंचनामा करें और तीन दिनों में समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को भेजें।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये ब्योरा जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचें ताकि राज्य सरकार नुकसान से प्रभावित किसानों की सहायता कर सके।

मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में इस संदर्भ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में कृषि फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए और संबंधित जिलों के नुकसान का ब्योरा दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कृषि विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, राजस्व विभाग की मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री टी. नटराजन और मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह एवं सचिव डॉ. विक्रांत पांडे मौजूद रहे।

जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक उछाल : अक्टूबर में 1.96 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वसूली, छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ आसान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर 2025 का महीना बेहद उत्साहजनक रहा। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन ने अब तक का सर्वाधिक स्तर छू लिया है। कुल 1.96 लाख करोड़ रुपये की वसूली के साथ यह एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यह पिछले साल की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत, व्यापारिक गतिविधियाँ और कर अनुपालन तीनों में स्थिर सुधार हो रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 1.89 लाख करोड़ और अगस्त में 1.86 लाख करोड़ रुपये था। लगातार तीन महीनों से राजस्व में यह वृद्धि यह दर्शाती है कि आर्थिक गति पुनः तेज हो रही है और करदाताओं में पारदर्शिता तथा ई-गवर्नेंस पर भरोसा लगातार बढ़ा है।

22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी 2.0 को इस तेजी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार ने इस संशोधित ढांचे में टैक्स प्रणाली को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब देश में केवल दो प्रमुख टैक्स स्लैब — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — लागू हैं। पहले मौजूद 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि, लग्जरी आइटम्स और 'सिन गुड्स' जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर विशेष 40 प्रतिशत जीएसटी दर रखी गई है।

इन बदलावों से बाजार में स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। लगभग 375 वस्तुओं, जिनमें किचन उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, होम अप्लायंसेज और आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, की कीमतें घट गई हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बाजार में मांग बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स वसूली भी स्वाभाविक रूप से ऊँची रही।

सरकार के अनुसार, जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2025 में रिफंड की राशि 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। वहीं, सकल घरेलू राजस्व (ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू) 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इंपोर्ट पर वसूले गए टैक्स में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 50,884 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। इस सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य के बीच सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। आज से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो गया है, जो पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित है। जिन कारोबारियों का मासिक टैक्स 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें अब मैन्युअल दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका आवेदन तीन कार्यदिवस के भीतर स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। यह सुविधा छोटे और मझोले उद्यमों (MSME सेक्टर) के लिए समय और संसाधनों की बड़ी बचत साबित होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन का यह बढ़ता हुआ रुझान केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का संकेत भी है। भारत का कर ढाँचा धीरे-धीरे विश्वस्तरीय पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले महीनों में राजस्व और निवेश दोनों में और मजबूती की संभावना जताई जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में यह रफ्तार और तेज होगी तथा चालू वित्त वर्ष के अंत तक जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के औसत मासिक स्तर तक पहुँच सकता है — जो भारतीय कर इतिहास का नया अध्याय साबित होगा।

चार मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार के लोगो की लॉन्चिंग टली, अब सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा एलान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह यानी 'लोगो' जारी होने का इंतजार अब कुछ और लंबा हो गया है। शनिवार को दिल्ली दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन चार मंत्रियों के दिल्ली से बाहर होने की वजह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब तक पूरी मंत्रिपरिषद की उपस्थिति में इस पर अंतिम सहमति नहीं बन जाती, तब तक इसे जारी नहीं किया जाएगा। अब लोगो की लॉन्चिंग बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही की जाएगी।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, चार प्रमुख मंत्री इन दिनों बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में व्यस्त हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान, संस्कृति और विकास की कहानी है, इसलिए इसे आधे अधूरे मन से जारी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री चाहती हैं कि इस प्रतीक में हर मंत्री की सहमति और दिल्ली की आत्मा का समावेश हो।

दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि लोगो डिजाइन को लेकर सरकार के भीतर लगातार चर्चा जारी है। इस प्रतीक को राजधानी की विरासत और आधुनिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाले रूप में तैयार किया गया है। इसमें संस्कृति, लोकतंत्र, नवाचार और नागरिक भागीदारी के भावों को एकसाथ जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह लोगो न केवल दिल्ली की पहचान बनेगा बल्कि इसे एक वैश्विक ब्रांड छवि भी प्रदान करेगा।

दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य को अपना आधिकारिक प्रतीक मिलने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में MyGov प्लेटफॉर्म पर लोगो डिजाइन करने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1,800 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रविष्टियाँ भेजीं। इन डिजाइनों में से कुछ सर्वश्रेष्ठ नमूनों को चयन समिति ने चुना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया। बताया जाता है कि जिस डिजाइन को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वह दिल्ली के 'इतिहास और इनोवेशन

के सह-अस्तित्व' को खूबसूरती से दर्शाता है।

मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार, रेखा गुप्ता चाहती हैं कि दिल्ली का यह प्रतीक भविष्य की राजधानी की दिशा दिखाए — एक ऐसी राजधानी जो पारदर्शी, आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिक-केंद्रित शासन की प्रतीक हो। लोगो में दिल्ली की धरोहरों जैसे लाल किला, इंडिया गेट या अशोक स्तंभ जैसे तत्वों के साथ विकास और प्रगति का प्रतीकात्मक भाव भी जोड़ा गया है।

दिल्ली के नाम को लेकर उठ रही नई चर्चाओं ने भी इस प्रतीक की लॉन्चिंग को और पेचीदा बना दिया है। एक ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अंग्रेजी में 'Delhi' की जगह 'Dilli' लिखे जाने की मांग उठाई है, तो वहीं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने राजधानी का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' करने का प्रस्ताव रखा है। विश्व हिंदू परिषद भी पहले ही इस मांग का समर्थन कर चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली कैबिनेट इन सुझावों पर भी विचार करेगी और संभव है कि लोगो में इन सांस्कृतिक भावनाओं को आंशिक रूप से परिलक्षित किया जाए।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह सिर्फ एक सरकारी पहचान नहीं होगा, बल्कि यह राजधानी की आत्मा का प्रतीक बनेगा — एक ऐसा चिन्ह जो दिल्ली की परंपरा और प्रगति दोनों को एक साथ जोड़ देगा। यह प्रतीक नागरिक भागीदारी, नवाचार और लोकतांत्रिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेगा। अधिकारी ने बताया कि इसकी डिज़ाइन भाषा आधुनिक और सौंदर्यपूर्ण है, जिसमें सादगी के साथ गरिमा और गौरव का भाव भी झलकता है।

अब दिल्लीवासियों की निगाहें बिहार चुनावों के बाद होने वाली दिल्ली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं। अनुमान है कि दिसंबर के प्रारंभ में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे लॉन्च करेंगी, तो राजधानी को उसकी पहचान देने वाला यह प्रतीक ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। यह न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई शुरुआत होगी, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक चेतना और उसकी आधुनिक दृष्टि को भी एक नया रूप देगा।

दिल्ली सरकार के इस निर्णय ने यह तो साफ कर दिया है कि लोगो सिर्फ एक चिन्ह नहीं, बल्कि राजधानी की आत्मा, उसकी कहानी और उसके भविष्य की दृष्टि का प्रतीक बनने जा रहा है। अब देखना यह है कि जब यह प्रतीक सार्वजनिक होगा, तो वह दिल्ली को किस नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा — एक परंपराओं से जुड़ी, फिर भी आधुनिकता की ओर अग्रसर राजधानी के रूप में।

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ राज्यपाल ने दी अभियोजन की मंजूरी

(जीएनएस)। चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिअद (शिरोमणि अकाली दल) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक और बड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मजीठिया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की 8 सितंबर को की गई सिफारिश के बाद लिया गया, जिससे अब विजिलेंस ब्यूरो को इस मामले को अदालत में आगे बढ़ाने की कानूनी अनुमति मिल गई है। यह मामला पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मजीठिया पर उनकी घोषित आय की तुलना में 1,200 प्रतिशत अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उनके पास लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां हैं, जिनका कोई वैध स्रोत नहीं बताया जा सका। विजिलेंस का दावा है कि यह संपत्ति उन्होंने 2013 में उजागर हुए सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अर्जित की थी, जिसमें लगभग

540 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन के प्रमाण मिले थे।तीन बार विधायक रह चुके मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को उनके अमृतसर स्थित आवास और देशभर में फैले 25 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। छापों के दौरान उनके घर और दफ्तर से डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 26 जून को मोहाली की अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। जांच की गंभीरता को देखते हुए यह रिमांड चार दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। 6 जुलाई को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद 22 अगस्त को विजिलेंस ब्यूरो ने अदालत में लगभग 40,000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 200 से अधिक गवाहों के बयान और कई दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच की जड़ें 2013 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उजागर किए गए 6,000 करोड़ रुपये के सिंथेटिक ड्रग रैकेट से जुड़ी हैं, जिसका सरगना पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला था। पूछताछ के दौरान भोला ने मजीठिया का नाम लिया था, जिसके बाद से ही यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में सुर्खियों में रहा।

हालांकि, ड्रग से जुड़े पुराने आरोप अदालतों ने सबूतों के अभाव में पहले ही खारिज कर दिए थे, लेकिन मौजूदा मामला भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर केंद्रित है। मजीठिया ने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि यह कार्रवाई अकाली दल को कमजोर करने की एक सोची-समझी रणनीति है।

अगस्त में मोहाली की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सितंबर में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान की थी।

अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद विजिलेंस ब्यूरो इस मामले को औपचारिक रूप से अभियोजन चरण में आगे बढ़ाएगा। सूत्रों के मुताबिक, मोहाली की सत्र अदालत में जल्द ही इस प्रकरण की अगली सुनवाई होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष अदालत से मजीठिया के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करेगा। इस मंजूरी को पंजाब की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बिक्रम मजीठिया लंबे समय से अकाली दल के प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। यह मामला अब न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी राज्य की सत्ता समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

लग्न समारोह में गोली चली, युवक की मौके पर मौत — हुड़दंग रोकने पर बढ़ा विवाद, तीन आरोपी फरार, गांव में तनाव

(जीएनएस)। रेवाड़ी जिले के पीथड़ावास गांव में शुक्रवार देर शाम खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब एक लग्न समारोह के दौरान हुड़दंग रोकने पर कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना इतनी अचानक हुई कि पूरे समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। मृतक की पहचान बधराणा गांव निवासी 30 वर्षीय इन्द्रजीत सिंह के रूप में हुई है, जो बिजली मिस्त्री के रूप में काम करता था।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात पीथड़ावास गांव में एक लग्न समारोह चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवक नशे की हालत में हुड़दंग कर रहे थे और शादी के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे। यह देख कर समारोह में शामिल इन्द्रजीत सिंह ने उन्हें समझाया कि वे शांति बनाए रखें और कार्यक्रम में अशांति न फैलाएं। लेकिन यह बात हुड़दंग कर रहे युवकों को नागवार गुज़री और बातों-बातों में कहासुनी झगड़े में बदल गई। इसी बीच उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकालकर इन्द्रजीत पर सीधा फायर कर दिया। गोली उसके गर्दन में लगी, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया।

गोली चलने के बाद हमलावरों ने 3-4 राउंड हवाई फायर भी किए और मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनते ही समारोह में भगदड़ मच गई। परिजन और ग्रामीण घायल इन्द्रजीत को अस्पताल ले जाने की कोशिश में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया।

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पास के गांव मनेठी के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है। शनिवार को जब मृतक के पोस्टमार्टम में देरी हुई, तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रामपुरा थाना के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। इससे गोपालदेव चौक पर लंबा जाम लग गया और यातायात ठप हो गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद दोपहर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और शाम को मृतक इन्द्रजीत सिंह का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव बधराणा में गमगीन माहौल में किया गया।

इन्द्रजीत सिंह की चार साल पहले शादी हुई थी और उसकी तीन साल की एक बेटी है। उसकी असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मनेठी गांव के तीन युवकों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

इस घटना के बाद पीथड़ावास और बधराणा दोनों गांवों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एक हंसते-खेलते परिवार का सहारा बने इन्द्रजीत की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिस समारोह में खुशी के गीत गूंजने थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और आंसुओं की लकीरें बची हैं — एक ऐसी रात, जो हमेशा पीथड़ावास के लोगों की स्मृतियों में दर्द की तरह दर्ज हो गई।

चलती बस में आग लगने पर कौन होगा जिम्मेदार? यात्रियों की सुरक्षा अब RTO की निगरानी में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में चलती बसों में आग लगने की घटनाओं ने सरकार का ध्यान एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा की ओर खींचा है। आए दिन सड़क पर बसों में अचानक आग भड़कने की खबरें आती रहती हैं, जिनमें कई बार यात्रियों की जान पर बन आती है। अब सरकार ने इस गंभीर समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अब से किसी भी बस को तभी फिटनेस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जब वह "बस बॉडी कोड" के सभी मानकों पर खरी उतरेगी। इन मानकों की जांच की जिम्मेदारी अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को सौंपी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें बसों में आग लगने की घटनाओं और यात्रियों की सुरक्षा को

लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में यह पाया गया कि देश के कई हिस्सों में अब भी बड़ी संख्या में बसें "बस बॉडी कोड" के मानकों का पालन नहीं करतीं। इस पर मंत्री ने सभी राज्यों के परिवहन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि बिना इन मानकों के पालन के किसी भी बस को सड़क पर उतरने की अनुमति न दी जाए।

क्या है बस बॉडी कोड और क्यों है जरूरी?

बस बॉडी कोड एक सुरक्षा मानक प्रणाली है जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2016 में तैयार किया था और 2017 में इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत बसों के निर्माण से लेकर अंदरूनी सुरक्षा उपकरणों तक के लिए कई अनिवार्य नियम तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य बसों को आग, दुर्घटना या आपात स्थिति में यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाना है। कोड के अनुसार, हर बस में कम से कम चार आपातकालीन दरवाजे (450 मिमी चौड़ाई के) होना आवश्यक है ताकि किसी भी स्थिति में यात्रियों की निकासी सुगमता से हो सके। बसों के अंदर फायर-रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS), तथा शीशे तोड़ने के लिए आपातकालीन हथौड़े रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही बस की पूरी वायरिंग और इंजन कंपार्टमेंट में ऐसे उपकरण लगाने होंगे जो आग फैलने से रोकें।

आरटीओ की भूमिका अब और सख्त

अब देशभर के आरटीओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बस का फिटनेस सर्टिफिकेट या नया रजिस्ट्रेशन तभी जारी होगा जब वह बस बॉडी कोड के सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी। किसी भी बस के निरीक्षण के दौरान यदि ये सुरक्षा उपकरण या सिस्टम नहीं पाए गए, तो उसका परमिट रद्द किया जा सकता है या रजिस्ट्रेशन स्थगित रहेगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने और पुराने बस ऑपरेटरों को 2025 तक का समय दिया है ताकि वे अपनी बसों को नए सुरक्षा कोड के अनुरूप अपग्रेड कर सकें। सितंबर 2025 के बाद इस कोड का उल्लंघन करने वाली बसों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों बढ़ रही हैं आग की घटनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि बसों में आग लगने की प्रमुख वजहें हैं—इलेक्ट्रिकल वायरिंग की खराब क्वालिटी, डीजल लीक, ओवरहीट इंजन, और बिना मेंटेनेंस के चलने वाले एयर-कंडीशनिंग सिस्टम। कई बस ऑपरेटर खर्च बचाने के लिए सस्ते पुर्जे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। राज्य सरकारों को भेजे गए नोटिस में नितिन गडकरी ने कहा है कि "यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि कोई बस सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती, तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे हादसों की स्थिति में अब केवल बस ऑपरेटर ही नहीं बल्कि निरीक्षण करने वाले संबंधित आरटीओ अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे।

इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि देशभर में बस ऑपरेटरों पर अपने वाहनों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप ढालने का दबाव बढ़ेगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, निजी बस संघों ने इस कदम को "जरूरी मगर महंगा" बताते हुए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है।

सरकार का यह नया सख्त कदम न सिर्फ बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, बल्कि यह देश के परिवहन ढांचे में एक नई पारदर्शिता और जिम्मेदारी की शुरुआत

दिल्ली-एनसीआर में छाई धुंध, यूपी-बिहार में बारिश के आसार, हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ठंडक का असर बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह दिल्ली की हवा धुंध और स्मॉग की परत में लिपटी नजर आई, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। वहीं, मौसम विभाग (IMD) ने 1 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है।दिल्ली में सुबह-सुबह घनी धुंध के कारण कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार धीमी रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हल्की हवा और रात के तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं, जिससे स्मॉग की परत गहराती जा रही है। रविवार तक तापमान में और 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम "मोंथा" के कारण देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके असर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर के अलावा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कानपुर, इटावा, अयोध्या, बाराबंकी, प्रयागराज, बहराइच, बलिया और गोरखपुर जैसे जिलों में 5 नवंबर तक रुक-रुककर वर्षा हो सकती है। वहीं, बिहार में भी 2 से 4 नवंबर के बीच आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 5 नवंबर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों — जैसे चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ — में भारी बर्फबारी की संभावना है।

केन्या में भीषण भूस्खलन से मचा कहर, 21 लोगों की मौत, 30 से अधिक लापता, हजारों बेघर हुए

(जीएनएस)। पश्चिमी केन्या के रिफ्ट वैली क्षेत्र में शनिवार को हुई भयानक प्राकृतिक आपदा ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। एल्गेयो मारक्वेट काउंटी के चेसोनगोच नामक पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही वर्षा ने इस क्षेत्र की मिट्टी को कमजोर कर दिया था, जिसके कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसक गया और नीचे बसे गांवों को निगल गया।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस भूस्खलन ने करीब एक हजार से अधिक मकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और अब खुले आसमान के नीचे रात गुज़ारने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज़ करने के लिए सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और पुलिस को लगाया है। भारी बारिश और कीचड़ के कारण राहत कार्यों में भारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन बचावकर्मी लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे

हैं।

स्थानीय निवासी स्टीफन किटनी ने एक स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि हादसे से ठीक पहले उन्होंने पहाड़ की ओर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ सुनते ही उन्होंने अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उनका पूरा घर मिट्टी के सैलाब में समा गया। उन्होंने कहा कि उनके कई पड़ोसी अब तक लापता हैं और पूरी बस्ती तबाह हो गई है।

गृह मंत्री किपचुम्बा मुर्कोमेन ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देगी। उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से घायल 30 लोगों को हवाई मार्ग से एल्डोरेट शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों की पहचान कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

चेसोनगोच और उसके आसपास के क्षेत्र को आपदा-प्रवण इलाका माना जाता है। इससे पहले वर्ष 2010 और 2012 में भी यहां भूस्खलन की घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2020 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया था, जिसमें एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर तक बह गया था।

स्थानीय भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र की पहाड़ियों की बनावट बेहद अस्थिर है और लगातार बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि यहां भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित वनों की कटाई ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। इस भयानक आपदा के बाद देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति और शीर्ष नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राहत एजेंसियां अब भी मलबे में दबी जानों को बचाने के लिए रात-दिन जुटी हैं, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। चेसोनगोच का यह भूस्खलन केन्या के इतिहास में दर्ज एक और दर्दनाक अध्याय बन गया है—जहां प्रकृति का कहर, जलवायु परिवर्तन की चेतावनी और मानव जीवन की असुरक्षा एक बार फिर भयावह रूप में सामने आई है।

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बहाने ठगी करने वाला गिरोह धराया, मोहाली पुलिस की बड़ी सफलता

(जीएनएस)। मोहाली। साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए मोहाली पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले मामले में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे मामले में एक 80 वर्षीय महिला को 2 करोड़ रुपये की डिजिटल ठगी से बचाया गया। दोनों मामलों की निगरानी एसएसपी हरमन हंस और एसपी रूपिंदर सोही ने की।

पहले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय कुमार निवासी डीसी कॉलोनी सिरसा (हरियाणा), सितेश निवासी निहार रेजीडेंसी (गुजरात) और चेतन निवासी गांव सगुरिया (गुजरात) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ये तीनों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जो गेमिंग ऐप्स के जरिए भोले-भाले लोगों को ऑनलाइन लुभाकर ठगी करते थे। इनके खिलाफ साइबर थाना फेज-7 में बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरोह के काम करने का तरीका बेहद

चालाकी भरा था। वे लोगों को गेमिंग ऐप में निवेश के बहाने झांसे में लेते, फिर उनके बैंक खातों से धीरे-धीरे रकम निकाल लेते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरड़ के सनी एन्क्लेव इलाके में एक घर से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मौके से तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 41 बैंक एटीएम कार्ड बरामद किए। इनमें हरियाणा ग्रामीण बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक सहित कई बैंकों के कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 9 चेकबुक और कई बैंक खातों के दस्तावेज भी मिले हैं।

जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह अब तक करीब 3 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी कर चुका है। पुलिस अब इनके बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेटवर्क कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इनके बाकी साथियों तक पहुंचा जा सके।

दूसरे मामले में पुलिस ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को साइबर ठगी से बचाया। आरोपी ठगों ने वीडियो कॉल के ज़रिए महिला को "डिजिटल गिरफ्तारी" का डर दिखाया और उनसे 12 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मांग की थी। वे तीन दिनों तक लगातार धमकाते रहे, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई। साइबर टीम ने तत्काल कार्रवाई कर महिला को ठगी से बचा लिया।

पुलिस ने दोनों घटनाओं के बाद नागरिकों को आगाह किया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, वेबसाइट या ऑनलाइन इनाम योजना पर भरोसा न करें। साइबर पुलिस ने अपील की है कि ठगी से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि साइबर अपराधी अब पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक सक्रिय हैं, और आम जनता को सतर्क रहकर ही अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।